

# भारत के युवाओं को पंख देना

भारत की विकास गाथा हमेशा से उसकी श्रम शक्ति द्वारा लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसने वैश्विक परिदृश्य में अपने लिए एक उल्लेखनीय स्थान बनाया है, और इस यात्रा में इसके मानव संसाधन की शक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

इस सफलता की कहानी को बल इस तथ्य से मिलता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। RBI-KLEMS के अनुसार, जहाँ 2004-2014 के बीच केवल 2.9 करोड़ नौकरियाँ सृजित हुईं, वहीं उसके बाद के दशक में 17 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ सृजित हुईं। EPFO के आंकड़ों के अनुसार, औपचारिकीकरण में भी तेज़ी आई है।

**सामाजिक सुरक्षा कवरेज** हालाँकि, वास्तविक परिवर्तन सामाजिक सुरक्षा कवरेज में हुआ है। 2015 में, केवल 19% भारतीय कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते थे। 2025 तक, यह संख्या बढ़कर 64.3% हो गई है, यानी 94 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचकर, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर कवरेज के सबसे तेज़ विस्तार में से एक माना है।

आगे देखते हुए, यह स्पष्ट है कि देश का भविष्य न केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर से, बल्कि हमारे द्वारा सृजित नौकरियों की गुणवत्ता, हमारे द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सुरक्षा और हमारे युवाओं को प्रदान किए जाने वाले अवसरों से भी तय होगा। बढ़ते स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रेरित अनिश्चितताओं, आपूर्ति-श्रृंखला में बदलावों और दुनिया भर में नौकरियों को आकार देने वाली अन्य कमजोरियों की वैश्विक पृष्ठभूमि में, भारत एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बिंदु पर खड़ा है।

भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़त देता है, जबकि पश्चिमी देशों में वृद्ध आबादी देखी जा रही है। वर्षों से, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश - इसकी युवा शक्ति - को इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। फिर भी, इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया। 2047 तक विकसित भारत के विजन की ओर बढ़ते हुए, हमारे सामने चुनौती स्पष्ट है: हमें 'संभावना' से 'समृद्धि' की ओर बढ़ना होगा।

इस पृष्ठभूमि में, रोजगार अब केवल एक आर्थिक संकेतक नहीं रह गया है; यह सम्मान, समानता और राष्ट्रीय शक्ति का आधार है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं को रोजगार योग्य बनाएं, उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ें, उन्हें वित्तीय साक्षरता से लैस करें और यह सुनिश्चित करें कि वे एक मज़बूत सामाजिक सुरक्षा जाल से सुरक्षित रहें। तभी हमारा जनसांख्यिकीय लाभ वास्तव में एक स्थायी राष्ट्रीय लाभांश में परिवर्तित हो सकता है।

**एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम** इस चुनौती का समाधान करने और आकांक्षा व अवसर के बीच की खाई को पाटने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना शुरू की है। शुरुआत में केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित और प्रधानमंत्री द्वारा अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित, यह योजना पैमाने और डिजाइन, दोनों ही दृष्टि से अतीत से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ, यह भारत के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिससे दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

इस योजना को इसकी संरचना ही विशिष्ट बनाती है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले पहले के कार्यक्रमों के विपरीत, यह योजना युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यम प्रतियर्थात्मकता की दोहरी चुनौती का एक साथ समाधान करती है। भाग A के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों (दो किशतों में ₹15,000 तक) और भाग B के अंतर्गत नियोक्ताओं (प्रति माह प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए ₹3,000 तक) दोनों को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, यह योजना कर्मचारियों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करती है और साथ ही व्यवसायों के लिए नियुक्ति जोखिम को भी कम करती है।

योजना का औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण की दिशा में स्पष्ट प्रयास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नए श्रमिकों को पहले दिन से ही सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार, यह योजना एक औपचारिक, सुरक्षित और उत्पादक श्रम बाजार की ओर एक संरचनात्मक धक्का है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन पर अतिरिक्त ध्यान भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और प्रेरक शक्ति है।

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना, योजना-आधारित हस्तक्षेपों से एक व्यापक रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बदलाव का संकेत देती है। यह उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और मेक इन इंडिया जैसी पूर्व पहलों से प्राप्त सीखों पर आधारित है और प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यवस्था में कार्य की बदलती प्रकृति को मान्यता देती है।

श्रमिकों और नियोक्ताओं का समर्थन करके, यह योजना यह मानती है कि रोजगार सृजन एक साझा जिम्मेदारी है। चूँकि भारत डिजिटल नवाचार को अपनाते हुए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यह योजना सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे। यहाँ तक कि सबसे छोटे उद्यम और कार्यबल में शामिल होने वाले नए व्यक्ति को भी राष्ट्रीय विकास की यात्रा में शामिल किया गया है।

**एक नया भारत** यह योजना एक नीतिगत घोषणा से कहीं बढ़कर है। यह पहल जनसांख्यिकीय लाभांश को सार्वजनिक समृद्धि में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह विकसित भारत के विजन को साकार करने की नींव का हिस्सा है, जहाँ हर युवा को सार्थक रोजगार मिले, हर काम में सम्मान हो और हर युवा को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले। रोजगार, अपने वास्तविक अर्थों में, राष्ट्र निर्माण है। इस पहल के साथ, मोदी सरकार अपनी इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है कि कोई भी आकांक्षा अधूरी नहीं रहेगी और कोई भी युवा अवसर से वंचित नहीं रहेगा।

# बिहार की हटाई गई मतदाता सूचियों में असामान्य पैटर्न: एक डेटा जांच

कई क्षेत्रों में लिंग जैसी श्रेणियों में और मृत्यु जैसे कारणों से असामान्य विलोपन दिखाई देते हैं

## DATA POINT

बिहार में 65 लाख से ज़्यादा हटाए गए मतदाताओं की भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार जारी की गई सूची के व्यापक विश्लेषण से कई विसंगतियाँ सामने आई हैं। ये पैटर्न संभावित रूप से समस्याग्रस्त मुद्दों की ओर इशारा करते हैं जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है। हटाए गए मतदाता आँकड़ों के हमारे विश्लेषण से विसंगतियों की आठ अलग-अलग श्रेणियाँ सामने आई हैं।

ECI ने विभिन्न भागों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए हटाए गए मतदाताओं की जाचकारी उपलब्ध कराई है। ये भाग विशिष्ट मतदान केंद्रों से संबंधित हैं। नीचे दी गई सूचियों में, मतदान केंद्रों के नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और जिले का नाम इसी क्रम में दिया गया है।

### मुख्य निष्कर्ष:

1. 80 विधानसभा क्षेत्रों में युवा मृत्यु दर असामान्य रूप से उच्च है
2. 127 विधानसभा क्षेत्रों में नाम हटाने में उच्च लैंगिक पूर्वाग्रह है
3. 1,985 विधानसभा क्षेत्रों में नाम हटाने की दर असामान्य रूप से उच्च है
4. 412 विधानसभा क्षेत्रों में अत्यधिक मृत्यु दर दर्ज की गई है
5. 7,216 विधानसभा क्षेत्रों में मृत्यु दर का उच्च अनुपात है
6. 973 विधानसभा क्षेत्रों में 100% मृत्यु-आधारित नाम हटाए गए हैं
7. 5,084 विधानसभा क्षेत्रों में "अनुपस्थित" मतदाताओं की संख्या अधिक है
8. 663 विधानसभा क्षेत्रों में "स्थायी रूप से स्थानांतरित" महिलाओं के संदिग्ध पैटर्न दिखाई देते हैं

### युवा मृत्यु दर

पैटर्न: विधानसभा क्षेत्र जहाँ 50 से अधिक लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, जिनमें से कम से कम आधे 50 वर्ष से कम आयु के हैं। आँकड़ों से बिहार भर में 80 विधानसभा क्षेत्रों/मतदान केंद्रों का पता चलता है जहाँ मृत्यु दर जनसांख्यिकीय मानदंडों का उल्लंघन करता है। सामान्य आबादी में, मृत्यु दर वृद्ध आयु समूहों की ओर अत्यधिक झुकी हुई है, जिससे युवा मृत्यु दर का उच्च अनुपात सांख्यिकीय रूप से असामान्य हो जाता है।

### पॉच चयनित असेम्बली भाग:

उर्दू मध्य विद्यालय चकदरिया, कहलगंज, भागलपुर: कुल मृत्यु 58, 50 वर्ष से कम आयु के 50 (86.2%)  
संत टेरेंसा कन्या मध्य विद्यालय, बगहा, पश्चिम चंपारण: कुल 70 मौतें, 59 50 वर्ष से कम आयु के (84.3%)  
मदरसा बिशनपुर, बैसी, पूर्णिया: कुल 61 मौतें, 48 50 वर्ष से कम आयु के (78.7%)  
उच्च विद्यालय हरारी, राजनगर, मधुबनी: कुल 58 मौतें, 50 वर्ष से कम उम्र के 45 (77.6%)  
प्राथमिक विद्यालय कानूनिया, रक्सौल, पूर्वी चंपारण: कुल 59 मौतें, 50 वर्ष से कम आयु के 45 (76.3%)  
चंपारण जैसे सीमावर्ती जिलों और अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी विसंगतियों का जमावड़ा है

### उच्च लिंग पूर्वाग्रह विलोपन

पैटर्न: ऐसे असेंबली भाग/स्टेशन जहाँ कम से कम 50 महिलाओं के नाम हटाए गए, और कुल विलोपन में 80% या उससे अधिक महिलाएँ थीं। एक चिंताजनक विसंगति, जहाँ 127 भागों में उच्च लैंगिक पूर्वाग्रह दिखाई दिया।

### पॉच चयनित भाग:

उत्कर्मित मध्य विद्यालय रमणिया पोखर, किशनगंज, किशनगंज: 105 कुल विलोपन, 97 महिलाएँ (92.4%)  
उच्च विद्यालय डिभियाँ, करगहर, रोहतास: 85 कुल विलोपन, 78 महिलाएँ (91.8%)  
उत्कर्मित मध्य विद्यालय बसही, राजपुर, बक्सर: 57 कुल विलोपन, 52 महिलाएँ (91.2%)  
बबन माथव मिडिल स्कूल, छपरा, सारण: 64 कुल विलोपन, 58 महिलाएँ (90.6%)  
उर्दू मध्य विद्यालय कुदारी, भभुआ, कैमूर: 64 कुल विलोपन, 57 महिलाएँ (89.1%)  
यह पैटर्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं के संभावित मताधिकार से वंचित होने का सुझाव देता है।

### असामान्य रूप से उच्च विलोपन दर

पैटर्न: 200 से अधिक विलोपन वाले भाग/मतदान केंद्र, सामान्य दरों से कहीं अधिक। 1,985 भागों में यह विसंगति दिखाई दे रही है, जो मतदाताओं के विलोपन के एक बड़े पैमाने को दर्शाता है।

### तीन चयनित भाग:

नवसृजित प्राथमिक विद्यालय निरंजना, गोपालगंज, गोपालगंज: कुल 641 विलोपन (599 स्थानांतरित, 39 मृत्यु, 3 अनुपस्थित)  
आंगनबाड़ी केंद्र जंगी रे के टोला, गोपालगंज, गोपालगंज: कुल 627 विलोपन (सभी 627 स्थानांतरित)  
उत्कर्मित मध्य विद्यालय बहुदरी, शाहपुर, भोजपुर: कुल 605 विलोपन (539 स्थानांतरित, 46 मृत्यु)  
गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र में यह घघनता विशेष रूप से चौकाने वाली है।

### अत्यधिक मृत्यु रिपोर्ट

पैटर्न: प्रति भाग 100 से अधिक मृत्यु रिपोर्ट। लगभग 412 भागों/मतदान केंद्रों ने इतनी अधिक संख्या में मृत्यु रिपोर्ट की।

### तीन चयनित भाग:

आदर्श मध्य विद्यालय बुधिया, बनमनखी, पूर्णिया: 181 मौतें (97 पुरुष, 84 महिला, औसत आयु 54.9)  
राजकीय पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, भागलपुर, भागलपुर: 165 मौतें (82 पुरुष, 83 महिला, औसत आयु 48.5)  
उत्कृष्ट मध्य विद्यालय पोखर भिंडा, मांडी, सारण: 162 मौतें (78 पुरुष, 84 महिला, औसत आयु 68.4)

### उच्च मृत्यु अनुपात

पैटर्न: 75% से अधिक नाम हटाए जाने का कारण मृत्यु है। 7,216 भाग/मतदान केंद्र इस पैटर्न को दर्शाते हैं, जहाँ मृत्यु के कारण नाम हटाए जाने की संख्या सामान्य जनसांख्यिकीय पैटर्न से कहीं अधिक है।

### तीन चयनित भाग:

राजकिया पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, भागलपुर: 166 विलोपन में से 165 मौतें (99.4%)  
उत्कर्मित मध्य विद्यालय पोखर भिंडा, मांडी, सारण: 191 विलोपन में से 162 मौतें (84.8%)  
उत्कर्मित मध्य विद्यालय धोबिनिया, किशनगंज: 171 विलोपन में से 158 मौतें (92.4%)

<b>सभी नाम मृत्यु के कारण हटाए गए</b> पैटर्न: सभी नाम केवल मृत्यु के कारण हटाए गए, कोई अन्य कारण नहीं। लगभग 973 मतदान केंद्रों/भागों में यह सांख्यिकीय रूप से असंभव परिदृश्य देखा गया है जहाँ प्रत्येक नाम मृत्यु के कारण हटाया गया है।	
<b>तीन चयनित भाग:</b> बालक प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर, बरहरा, भोजपुर: सभी 126 नाम मृत्यु के कारण हटाए गए (औसत आयु 66.0 वर्ष) उत्कर्मित मध्य विद्यालय नवकाटोला, भोरे, गोपालगंज: सभी 124 नाम मृत्यु के कारण हटाए गए (औसत आयु 56.9 वर्ष) उत्कर्मित मध्य विद्यालय फुलहारा, हाजीपुर, वैशाली: सभी 118 नाम मृत्यु के कारण हटाए गए (औसत आयु 66.8 वर्ष)	
<b>सामुहिक "अनुपस्थित" वर्गीकरण</b> पैटर्न: प्रत्येक भाग/केंद्र पर 50 से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित के रूप में चिह्नित किया गया। 5,084 केंद्रों में यह पैटर्न दिखाई देता है।	
<b>तीन चयनित भाग:</b> कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज, गोपालगंज: 457 अनुपस्थित चिह्नित (215 पुरुष, 242 महिला, औसत आयु 42.2) मध्य विद्यालय प्राणपट्टी, कस्बा, पूर्णिया: 351 अनुपस्थित चिह्नित (208 पुरुष, 143 महिला, औसत आयु 26.3) सामुदायिक भवन चौहट्टा, हाजीपुर, वैशाली: 339 अनुपस्थित चिह्नित (177 पुरुष, 162 महिला, औसत आयु 41.9) संदिग्ध महिला "स्थानांतरित"	
पैटर्न: कम से कम 60 मतदाताओं को स्थानांतरित के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनमें से 75%+ महिलाएँ हैं। लगभग 663 भाग/स्टेशनों में यह पैटर्न दिखाई देता है जहाँ महिलाओं को असमान रूप से "स्थानांतरित" निवास के रूप में चिह्नित किया गया है।	
<b>तीन चयनित क्षेत्र:</b> पंचायत भवन सिकटिया, कुचायकोट, गोपालगंज, गोपालगंज: 80 स्थानांतरित मतदाता, सभी 80 महिलाएँ (100%, औसत आयु 29.9) उत्कृष्ट मध्य विद्यालय चतुर बगहा, गोपालगंज, गोपालगंज: 63 स्थानांतरित मतदाता, सभी 63 महिलाएँ (100%, औसत आयु 30.0) रामरतन शाही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोपालगंज, गोपालगंज: 71 स्थानांतरित मतदाता, 70 महिलाएँ (98.6%, औसत आयु 30.5)	
<b>भौगोलिक और जनसांख्यिकीय प्रतिरूप</b> सीमावर्ती जिले: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट पूर्णिया, किशनगंज और चंपारण जिलों में विसंगतियों की उच्च सांद्रता।	
गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र: कई विसंगति श्रेणियों में उच्च सांद्रता, संभावित अनियमितताओं का संकेत देती है। अल्पसंख्यक-केंद्रित क्षेत्र: कई प्रभावित क्षेत्र महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में प्रतीत होते हैं। युवा महिलाएँ: कई श्रेणियाँ युवा महिला मतदाताओं (18-29 वर्ष) पर असमानुपातिक प्रभाव दिखाती हैं।	
<b>कई पैटर्न सांख्यिकीय संभावना को चुनौती देते हैं:</b> मृत्यु के कारण 100% नाम हटाए जाने वाले बृ्थ जनसांख्यिकीय रूप से समस्याग्रस्त हैं। 90% से अधिक नाम हटाए जाने वाले लिंग अनुपात प्राकृतिक जनसंख्या पैटर्न के विपरीत हैं। 75% से अधिक युवा मृत्यु दर मृत्यु दर के आंकड़ों के विपरीत है। विशिष्ट बृ्थों में बड़े पैमाने पर "अनुपस्थित" वर्गीकरण की पुनः जाँच की आवश्यकता है।	
<b>कुछ प्रश्न उठाए जाने आवश्यक हैं:</b> मतदाताओं को मृत के रूप में चिह्नित करने से पहले क्या सत्यापन किया गया था? कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में विसंगतियों की अधिकता क्यों दिखाई देती है? महिलाओं को अधिक क्यों बाहर रखा गया है? और कई हिस्सों में 'मृत' श्रेणी के तहत युवा मतदाताओं का इतना बड़ा हिस्सा क्यों बाहर रखा गया है?	
चुनाव आयोग को मतदान केंद्रों की जाँच करनी चाहिए और हटाए गए मतदाताओं का सत्यापन करना चाहिए और यदि उन्हें गलती से बाहर रखा गया है तो बहिष्कृत मतदाताओं को बहाल करने का कोई तरीका स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने के लिए, दावों और आपत्तियों की समय सीमा को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए।	
ये प्रश्न नागरिक समाज कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के सहयोग से तैयार किए गए थे। डेटा को डेटामीट समुदाय के सदस्य, थेजेश जीएन की मदद से संकलित किया गया था	

*To Read UPSC Edition on daily basis with MCQ's so please message at 8168305050*